Belgium	6985	3442
Denmark	116	62
France	7824	8558
Germany	1411	1285
Netherlands	6762	2836
Ireland	137	301
Portugal	3322	3900
Greece	6690	8318
Norway	83	40
Switzerland	130	193
Singapore	9704	15454
Hong Kong	53220	40593
U.A.E.	4712	5330
Sri Lanka	2210	3482
Others	31127	15203
TOTAL	243960	209025

नई आर्थिक नीति का बेरोजगारी पर प्रभाव

*206. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे. शाह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मई, 1994 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रैस" में "इम्पेक्ट आफ न्यू इकानामिक पालिसीज आन अनएम्प्लायमेंट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति के कारण देश में बरोजगार व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार बेरोजगार व्यक्तियों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये वर्तमान पूंजी प्रधान आर्थिक नीति के स्थान पर श्रम प्रधान नीति लाने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री **पी.ए. संगमा**) : (क) से (ङ) जी, हां योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार, मार्च, 1990 तथा मार्च, 1993 के अंत में बेरोजगारी का बैकलाग क्रमशः 12.7 मिलियन तथा 17.6 मिलियन था। चालू संरचनात्मक सुधारों से रोजगार की

वृद्धि दर में सुधारों की आरम्भिक अवस्थाओं में बहुत कम अवधि के लिए धीमापन आ सकता है किन्तु उनसे मध्यम काल में पर्याप्त उच्चतर तथा विस्तृत वृद्धि होने की संभावना है, अतः रोजगार वृद्धि पर प्रभाव सकारात्मक होगा ।

सरकार भावी आर्थिक सुधारों के किन्हीं सम्भावित प्रतिकूल परिणामों से अवगत है तथा इसलिए उसने सुधारों की सामाजिक लागतों को न्यूनतम करने की सचेष्ट नीति अपनाई है । समग्र आर्थिक संशोधन के माध्यम से प्राप्त युक्तिचालन का अनुसरण करते हुए 1993–94 के दौरान सामाजिक क्षेत्रों के लिए आवंटनों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई । 1994–95 के बजट में सामाजिक क्षेत्रों, ग्रामीण विकास तथा गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के लिए उच्चतर आवंटनों की इस प्रक्रिया को आगे ले जाया गया है । 1991 से मुद्रास्फीति की दर को कम करने में सरकार की सफलता गरीबों के लिए लाभप्रद हो सकती हैं । आर्थिक सुधारों का मूल उद्देश्य आय तथा उत्पादक रोजगार में तीव्र वृद्धि के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में तीव्र तथा सतत सुधार करना तथा 1991 की अभूतपूर्व संकट स्थिति के पश्चात् आर्थिक वृद्धि के संवेग को पुनः स्थापित करना है । गरीबी तथा बरोजगारी अल्प रोजगारी के तीव्र उपशमन के लिए अत्यधिक एवं गहन श्रम वृद्धि अनिवार्य है । सरकार द्वारा आरम्भ किए गए संरचनात्मक समायोजन तथा आर्थिक सुधार उत्पादकता, दक्षता, संसाधनों तथा प्रतियोगी बाजार प्रवृत्तियों की विधा की पूर्ण उपयोगिता प्राप्त करने हेतु है ।

Funds earmarked for PDS during Eighth Five Year Plan

*207. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the funds provided by Government for the Public Distribution System (PDS) during the Eighth Five Year Plan are inadequate to meet the growing needs;

(b) if so, the funds earmarked during the Eighth Five Year Plan;

(c) the allocations made to different States under PDS; and

(d) the year-wise details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) to (d) Funds for various sectoral programmes including the Public Distribution System (PDS) are allocated taking into account the inter-se requirements of all the programmes and the overall availability of resources. The Plan Schemes under the Public Distribution System are meant to supplement the efforts made by the State Governments and U.T. Administrations who are responsible for all operational aspects of the PDS. A statement showing the actual expenditure during the year 1992-93 and 1993-94 as well as the approved outlays for the year 1994-95, 1995-96 and 1996-97 is at statement-I. (see below)

Financial assistance to States/UTs is provided based on the proposals received from them as also taking into account the requirements of all the States/UTs. Funds sanctioned under the Schemes to States/UTs during 1992-93 and 1993-94 are given in statement-II and III.